भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 242
04 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन से सहायता

242. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में कृषि संबंधी पहलों के लिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय समर्थन एवं सहायता की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन एजेंसियों के सहयोग से भारत में जलवायु-स्मार्ट कृषि, सतत विकास और कृषि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाली विशिष्ट परियोजनाएं क्या हैं, साथ ही उनके उद्देश्यों और प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) सतत कृषि पद्धतियों और जैव विविधता संरक्षण रणनीतियों को लागू करने के लिए इन एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या कृषि में उभरती चुनौतियों का समाधान करने और कृषक समुदायों पर जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए इन एजेंसियों के साथ साझेदारी करने की कोई योजना है; और

(ङ) प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगातार हो रहे फसल नुकसान को देखते हुए कुट्टनाड और वायनाड के लिए विशेष रूप से तैयार की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और विश्व बैंक भारत में केंद्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र दोनों के तहत कृषि परियोजनाओं को ऋण, क्षमता निर्माण पहल और तकनीकी सहायता सहित समर्थन प्रदान करते हैं। भारत सरकार वर्तमान में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ, इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ कई परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। इन सहयोगात्मक प्रयासों, उनके उद्देश्यों और की गई प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी - विशेष रूप से भारत में जलवायु-स्मार्ट कृषि, सतत विकास और कृषि-जैव विविधता संरक्षण के संबंध में - अनुबन्ध में प्रदान की गई है।

(ग) और (घ): आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) एडीबी और विश्व बैंक के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो इन अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ चल रहे सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाए रखता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एफएओ के साथ समन्वय करता है। भारत सरकार इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए नियमित संयुक्त समीक्षा, कार्यशालाओं और उच्च स्तरीय राज्य यात्राओं के माध्यम से निरंतर जुड़ाव और निरीक्षण सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, बाहरी सहायता की आवश्यकता वाली किसी भी परियोजना को संबंधित वित्त पोषण एजेंसियों को प्रस्तुत करने से पहले मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी तरह से जांचा जाता है।

(ङ): केरल सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुट्टनाड और वायनाड में फसल की हानि को हल करने के लिए कोई विशिष्ट परियोजनाएं नहीं हैं। हालांकि, विश्व बैंक केरल जलवायु अनुकूल कृषि-मूल्य श्रृंखला आधुनिकीकरण परियोजना का समर्थन कर रहा है जिसमें 200 मिलियन डॉलर का ऋण शामिल है।

अनुबन्ध

एफएओ, एडीबी और डब्ल्यूबी एजेंसियों के सहयोग से चल रही विशिष्ट परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 04.02.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 242 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबन्ध

क्रमांक	**परियोजना का शीर्षक**	**परियोजना के उद्देश्य और प्रगति**
खाद्य एवं कृषि संगठन		
1	गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने तथा इमारती लकड़ी और गैर-इमारती कृषि वानिकी प्रजातियों के लिए नर्सरियों के प्रमाणीकरण में सहायता	प्रमाणन से संबंधित लंबित तकनीकी मुद्दों और बाधाओं को दूर करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों और हितधारकों को एक साथ लाना, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री और नर्सरियों को प्रमाणित करने के लिए मानक प्रोटोकॉल विकसित करना और प्रमाणन के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करना। लकड़ी और गैर-लकड़ी कृषि वानिकी प्रजातियों को बढ़ाने के लिए मानक प्रोटोकॉल का मसौदा तैयार किया। एजेंसियों के प्रमाणन/मान्यता के लिए प्रोटोकॉल और मानकों का मसौदा तैयार किया। वन बीज प्रमाणन प्रणाली और भारत में वन नर्सरी की स्थिति पर श्वेत पत्र विकसित किए। प्रोटोकॉल को मान्य करने के लिए 5 क्षेत्रीय परामर्श कार्यशालाएँ आयोजित कीं।
2	ओडिशा और अन्य वर्षा सिंचित क्षेत्रों में समुदाय-प्रबंधित बीज प्रणालियों (सीएमएसएस) के माध्यम से स्थानीय भूमि प्रजातियों/किसानों की किस्मों (एलआर/एफवी) के गुणवत्तायुक्त बीजों के लिए समर्थन	बीज मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अंतिम चरण में कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा ओडिशा में मिलेट के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिए एसओपी का विस्तार करना। ओडिशा में भूमि संवर्धन/किसान किस्मों के वर्तमान परिदृश्य की जांच करने के लिए सर्वेक्षण किया गया। तीन परियोजना स्थलों और राज्य स्तर पर विभिन्न (बीज) अभिनेताओं की पहचान की गई। तीन परियोजना जिलों बरगढ़, मयूरभंज और कोरापुट के लिए निःशुल्क पूर्व सूचित सहमति (एफपीआईसी) प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।
3	वैश्विक पर्यावरणीय लाभ और महत्वपूर्ण जैव विविधता और वन परिदृश्य के संरक्षण के लिए भारतीय कृषि में परिवर्तन (एफएसपी)	राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय लाभ की प्राप्ति में सहायता करने तथा महत्वपूर्ण जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए भारत के कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करना। मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड और मिजोरम में चार ग्रीन लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान (जीएलएमपी) विकसित किए गए, जो कृषि-पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, भूमि बहाली और जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित हैं। परिवारों ने

क्रमांक	परियोजना का शीर्षक	परियोजना के उद्देश्य और प्रगति
		सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में भाग लिया, जिसमें ओडिशा सबसे आगे रहा। परिवारों को पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में विशेष रूप से ग्रीन-एग फार्मर फील्ड स्कूलों से महिलाओं को लाभ मिलता है।
4	पंजाब, हरियाणा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में चावल-गेहूँ प्रणालियों में परिवर्तन के माध्यम से भारत में सतत खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना (एफएसपी)	भारत में चावल और गेहूँ की खेती वाले क्षेत्रों में सतत और स्वस्थ खाद्य प्रणालियों के एकीकृत मॉडल को मुख्यधारा में लाना। कार्यान्वयन के पहले वर्ष में, 9,000 हेक्टेयर के लिए हस्तक्षेप की योजना बनाई गई थी। दिसंबर 2024 तक, 2,351 हेक्टेयर (पंजाब: 1,090.55 हेक्टेयर, हरियाणा: 446.4 हेक्टेयर, छत्तीसगढ़: 460 हेक्टेयर, ओडिशा: 354.43 हेक्टेयर) ने सफलतापूर्वक सतत प्रथाओं को अपनाया है। 2,030 किसानों (पंजाब: 343, हरियाणा: 388, छत्तीसगढ़: 770, ओडिशा: 529) ने इस पहल के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
5	भारत में उप-राष्ट्रीय स्तर पर संवर्धित जलवायु वित्त पोषण के लिए कृषि क्षेत्र की तैयारी (जीसीएफ आरपी)	कृषि और जलवायु निवेश योजनाएँ तैयार करना जो भारत में उप-राष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र की जलवायु परिवर्तन कार्यनीतियों और नीतियों के कार्यान्वयन का समर्थन करती हैं। चार राज्यों की कृषि प्रोफ़ाइल और जलवायु परिदृश्य तैयार किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने कृषि वानिकी प्रस्ताव के लिए प्रमुख इकाई बनने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं को हरा-भरा बनाने के लिए प्रमुख इकाई बनने पर सहमति व्यक्त की है। खाद्य हानि और बर्बादी तथा जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए फसलोपरांत मूल्य श्रृंखलाओं का मूल्यांकन।
6	भारत के तटीय क्षेत्रों में प्रवासी और कमजोर परिवारों की जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता को बढ़ाना	जलवायु परिवर्तन के प्रति ग्रामीण परिवारों की तन्यकता को सुदृढ़ करना, संकट के समय पलायन के दबाव को कम करना और पलायन परिणामों में सुधार करना, विशेष रूप से ओडिशा राज्य के तटीय क्षेत्रों और तेलंगाना राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों की अक्षमताओं को दूर करने पर ध्यान देना। तेलंगाना के चार जिलों में एक त्वरित जेन्डर - और आयु-संवेदनशील जलवायु भेद्यता और जोखिम मूल्यांकन (वीआरए) आयोजित किया गया। ओडिशा में, गंजम और

क्रमांक	परियोजना का शीर्षक	परियोजना के उद्देश्य और प्रगति
		केंद्रपाड़ा के तटीय जिलों में एक समान वीआरए आयोजित किया गया था। ओडिशा राज्य ने जेपी कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने और विभागों के बीच समन्वय में सुधार करने के लिए एक तकनीकी संचालन समूह (टीएसजी) का गठन किया है। गंजम और केंद्रपाड़ा में दो जिला स्तरीय समितियाँ (डीएलसी) स्थापित की गई हैं। दोनों राज्यों में जमीनी हस्तक्षेप के लिए चुने गए गाँवों का आधारभूत सर्वेक्षण चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम संचालन समिति (पीएससी) का गठन किया गया, और पहली बैठक 3 अक्टूबर 2024 को हुई।
7	आंध्र प्रदेश की जलकृषि को टिकाऊ, कम उत्सर्जन वाली और जलवायु अनुकूल खाद्य प्रणाली (एफएसपी) में बदलना	उत्पादन स्तर पर और मूल्य श्रृंखला में पर्यावरणीय गिरावट को कम करने वाले संधारणीय और कम पदचिह्न वाले जलीय कृषि उत्पादन प्रणालियों के माध्यम से एपी में स्थलीय/जलीय परिदृश्यों के एकीकृत प्रबंधन का समर्थन करना। इसके अतिरिक्त, उत्पादन और जलवायु लचीलापन को संधारणीय रूप से बढ़ाना, उत्पादकों की आय और लचीलापन बढ़ाना, जोखिम कम करना और जलीय कृषि के लिए पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण (ईएए) का पालन करते हुए समान तरीके से स्वस्थ, किफायती भोजन की वैश्विक जरूरतों को पूरा करना। जीईएफ8 पूर्ण परियोजना प्रस्ताव को समीक्षा/समर्थन के लिए जीईएफ सचिवालय को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है।
8.	मध्य भारत परिदृश्य (मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र) में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली का समर्थन (एफएसपी)	मध्य भारतीय परिदृश्य में एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन दृष्टिकोण का समर्थन करना, जिसमें क्षरित वन और कृषि भूमि की बहाली और बेहतर प्रबंधन, तथा दीर्घकालिक रूप से जैव विविधता संरक्षण, कार्बन पृथक्करण और पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए स्थायी आजीविका को अपनाना शामिल है। जीईएफ ऑपरेशनल फोकल प्वाइंट (एमओईएफ एंड सीसी) ने जीईएफ 8 परियोजना पहचान फॉर्म (पीआईएफ) को जीईएफ परिषद की मंजूरी के लिए सिफारिश के साथ भेजा।

क्रमांक	परियोजना का शीर्षक	परियोजना के उद्देश्य और प्रगति
9.	एकीकृत भूदृश्य प्रबंधन के माध्यम से पशुपालकों की लचीलापन क्षमता को सक्षम बनाना	लिंग-समावेशी एकीकृत भूदृश्य प्रबंधन के माध्यम से भूमि क्षरण को कम करना तथा पशुपालकों की तन्यकता को बढ़ाना। जीईएफ ऑपरेशनल फोकल प्वाइंट (एमओईएफ एंड सीसी) ने जीईएफ 8 परियोजना पहचान फॉर्म (पीआईएफ) को जीईएफ परिषद के अनुमोदन के लिए सिफारिश के साथ भेजा।
एशियाई विकास बैंक		
1	भारतीय कृषि प्रणाली के परिवर्तन में सहायता ($3.0 मिलियन अनुदान)	तकनीकी सहायता (टीए) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) और अन्य प्रासंगिक कार्यान्वयन एजेंसियों को पाइपलाइन परियोजना की तैयारी, अपस्ट्रीम ज्ञान विकास और भारत की कृषि प्रणाली के संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण को प्राप्त करने में मदद करने के लिए कई परिवर्तनकारी पहलों के लिए क्षमता निर्माण के लिए समर्थन देती है। 27.01.2025 तक 75,310 डॉलर वितरित किए गए।
2	हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय सिंचाई और मूल्य अतिरिक्त (एचपीएसएचआईवीए) ($133 मिलियन ऋण; कुल परियोजना $163 मिलियन)	जलवायु स्मार्ट उत्पादन तकनीक और एकीकृत कीट प्रबंधन में किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना, तथा परियोजना क्षेत्रों के 6,000 हेक्टेयर में एकीकृत खेती को अपनाना। 27.01.2025 तक 14.5 मिलियन डॉलर वितरित किए गए।
3	महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एग्रीबिजनेस नेटवर्क (मैग्नेट) ($100 मिलियन ऋण; कुल परियोजना लागत $142 दस लाख)	यह परियोजना 200 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और 100 मूल्य श्रृंखला संचालकों (वीसीओ) को सहायता प्रदान करती है और इससे 200,000 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य बागवानी उत्पादन मूल्य में वृद्धि करना और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना है। 27.01.2025 तक 32.41 मिलियन डॉलर वितरित किए गए।
विश्व बैंक		
1	असम कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना (ऋण राशि 200 मिलियन डॉलर)	चयनित कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में मूल्य संवर्धन और लचीलापन बढ़ाने के लिए, छोटे किसानों और कृषि-उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित करना और असम की कोविड-19 प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाना। जनवरी 2025 के अंत

क्रमांक	परियोजना का शीर्षक	परियोजना के उद्देश्य और प्रगति
		तक 161.70 मिलियन डॉलर वितरित किए गए।
2	तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ($318 मिलियन)।	सिंचित कृषि की उत्पादकता और जलवायु लचीलापन बढ़ाने, जल प्रबंधन में सुधार करने और तमिलनाडु के चयनित उप-बेसिन क्षेत्रों में किसानों और कृषि-उद्यमियों के लिए बाजार के अवसरों को बढ़ाने के लिए जनवरी 2025 के अंत तक 229.53 मिलियन डॉलर वितरित किए गए।
3	एपी एकीकृत सिंचाई एवं कृषि परिवर्तन परियोजना ($62.6 मिलियन)	आंध्र प्रदेश के चयनित जिलों में छोटे किसानों की कृषि उत्पादकता, लाभप्रदता और जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए जनवरी 2025 के अंत तक 28.43 मिलियन डॉलर वितरित किए जाएंगे।
4	जलवायु अनुकूल कृषि के लिए ओडिशा एकीकृत सिंचाई परियोजना ($135.3 मिलियन)	ओडिशा के चयनित जिलों में कृषि उत्पादन में तेजी लाने और विविधता लाने तथा जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए जनवरी 2025 के अंत तक 46.91 मिलियन डॉलर वितरित किए जाएंगे।
5	हिमाचल प्रदेश में स्रोत स्थिरता और जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि के लिए एकीकृत परियोजना ($80 मिलियन)	हिमाचल प्रदेश में चयनित ग्राम पंचायतों में अपस्ट्रीम वाटरशेड प्रबंधन में सुधार और कृषि जल उत्पादकता में वृद्धि करना। जनवरी 2025 के अंत तक 47.22 मिलियन डॉलर वितरित किए गए।
6	छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण एवं त्वरित कृषि विकास परियोजना ($85 मिलियन)	छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लक्षित परिवारों में आय के अवसरों और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में सुधार करना। जनवरी 2025 के अंत तक 1.12 मिलियन डॉलर वितरित किए जाएंगे।
7	नवीन विकास के माध्यम से कृषि लचीलेपन के लिए जलग्रहण क्षेत्रों का पुनरुद्धार ($115 मिलियन)	किसानों की लचीलापन बढ़ाने और भाग लेने वाले राज्यों के चयनित वाटरशेड में मूल्य श्रृंखलाओं को समर्थन देने के लिए बेहतर वाटरशेड प्रबंधन को अपनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करना। जनवरी 2025 के अंत तक 39.84 मिलियन डॉलर वितरित किए गए।
8	त्रिपुरा ग्रामीण आर्थिक विकास और सेवा वितरण परियोजना	त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्रों के लिए सेवाओं और आर्थिक अवसरों में सुधार करना। जनवरी 2025 के अंत तक

क्रमांक	परियोजना का शीर्षक	परियोजना के उद्देश्य और प्रगति
	($140 मिलियन)	4.32 मिलियन डॉलर वितरित किए जाएंगे।
9	उत्तराखंड जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि परियोजना ($96.2 मिलियन)	उत्तराखंड के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में पर्वतीय कृषि उत्सर्जन को प्रतिस्पर्धी और लाभप्रद बनाने के लिए उत्पादन प्रणाली के लचीलेपन में सुधार करना। जनवरी 2025 के अंत तक 0.89 मिलियन डॉलर वितरित किए जाएंगे।
10	केरल जलवायु लचीला कृषि मूल्य श्रृंखला आधुनिकीकरण परियोजना ($200 मिलियन)	कृषि क्षेत्र की लचीलापन और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना ।
11	उत्तर प्रदेश कृषि विकास एवं ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना ($325.1 मिलियन)	उत्तर प्रदेश के चयनित क्षेत्रों में बेहतर फसल उत्पादकता, जलवायु लचीलापन और कृषि-खाद्य प्रणालियों के व्यावसायीकरण के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना।
12	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना का त्वरित विकास - चरण II ($148 मिलियन)	पश्चिम बंगाल के परियोजना क्षेत्रों में बेहतर सिंचित कृषि के लिए जल उपलब्धता को बढ़ाना और जल उपयोगकर्ता संघों को मजबूत करना। जनवरी 2025 के अंत तक 11.85 मिलियन डॉलर वितरित किए जाएंगे।

*****